भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3747
दिनांक: 12.08.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ

प्रश्न 3747: श्री मुकेशकुमार चन्द्रकान्त दलाल

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के अंतर्गत ड्रोन मैपिंग कवरेज ने संपत्ति कार्डों के सटीक वितरण में योगदान दिया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या स्वामित्व योजना ने ग्रामीण शासन में सुधार लाने और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के कार्यान्वयन को बढ़ाने में योगदान दिया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इन संपत्ति कार्डों की तैयारी और वितरण से ग्रामीण महिलाओं को कानूनी संपत्ति के स्वामित्व के साथ सशक्त बनाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या इस योजना से संपत्ति विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है और यदि हाँ, तो गुजरात सहित राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) इस योजना ने किस प्रकार ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाते हुए संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच प्रदान की है, इसका ब्यौरा क्या है?

उत्Åर

पंचायती राज राज्À मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) जी हाँ, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग कवरेज ने संपत्ति कार्डों के सटीक वितरण में योगदान दिया है। 6 अगस्त 2025 तक, लक्षित 3.44 लाख गांवों में से 3.26 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; 1.73 लाख गांवों में 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

(ख) इस प्रकार से स्वामित्व योजना ने ग्रामीण शासन में सुधार लाने और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के कार्यान्वयन को बढ़ाने में महत्वपूर्णयोगदान दिया है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की सभी उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली ड्रोन छवियों को मंत्रालय के ग्राम मंचित्र एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये डिजिटल छवियां ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को सुविधाजनक

बनाने के लिए निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करती हैं। हालाँकि, मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

ग) पंचायती राज मंत्रालयकेपास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश ने राजस्व विभाग द्वारा पत्र संख्या एफ 2-5/2021/सात/शा.-7 दिनांक 05.04.2021 के तहत जारी स्वामित्व सर्वेक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड में महिला मालिकों का नाम शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, हालांकि, महिला संपत्ति मालिकों की संख्या के संबंध में मंत्रालय के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी राज्य द्वारा ऐसा कृत्य मंत्रालय के ध्यान में नहीं है।

घ) यह योजना सटीक संपत्ति कार्डों के सृजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे स्पष्ट स्वामित्व अभिलेख प्रदान करके संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाई जा सके। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना, लेन-देन को सुगम बनाना तथा आबादी क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को सशक्त करना है। हालांकि, संपत्ति विवादों में कमी से संबंधित कोई आंकड़ा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ) स्वामित्व योजना ने संपत्ति कार्ड धारकों के लिए संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने में योगदान दिया है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 1307 करोड़ रुपये के 9931 ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

****